GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.66
TO BE ANSWERED ON THE 8TH FEBRUARY, 2022

ALARMING RISE IN OMICRON CASES IN THE COUNTRY

66 SHRI T.G. VENKATESH:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE** be pleased to state:

(a) whether the Ministry has taken note of the alarming rise in the spread of Omicron variant of COVID-19 cases in the country that is paralyzing the health conditions of the people;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps being taken by Government to obviate this in the country?

ANSWER
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR MANSUKH MANDAVIYA)

(a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 66* FOR 8TH FEBRUARY, 2022

(a) to (c): With the reporting of Omicron Variant, a highly mutated variant of SARS-CoV-2 virus and its classification as a Variant of Concern (VoC) by the World Health Organization (WHO), the Union Ministry of Health & FW revised its 'Guidelines for international arrivals'. Following a risk based approach, provisions for mandatory pre-departure & post arrival RT-PCR testing on day 8th of arrival and a mandatory home quarantine for 7 days have been made in the present guidelines for all international travelers to India.

Ministry of Health & Family Welfare continues to provide technical guidance for managing various aspects of COVID-19 including containment and surveillance, testing, clinical management protocols, post-COVID sequale, etc. The clinical management protocols have also been disseminated under Ministry of Health & FW's Center of Excellence initiative for all States collaboration with AIIMS, Delhi and Indian Medical Association.

Besides regular review meetings at the level of Union Health Minister with all relevant stakeholders including subject experts, review meetings with States/UTs through video conferencing have been conducted regularly to review preparedness and response measures to address COVID-19 pandemic. States/UTs have been advised to undertake the following activities:

- Strict monitoring of International travelers in the community.
- Contact tracing of positive individuals & follow up for 14 days.
- Genome sequencing of positive samples through INSACOG Labs in a prompt manner.
- Continued monitoring of areas where cluster of positive cases emerge.
- Further strengthening of COVID-19 testing infrastructure and ensuring early identification of cases through adequate testing across the States.
- Ensuring preparedness of health infrastructure (availability of ICU, oxygen supported beds, ventilators, etc.) and upgrading health infrastructure under ECRP-II including in rural areas and for pediatric cases.
- Commissioning all PSA plants, ensuring sufficient logistics, drugs etc.
- Ensuring COVID-19 vaccination for the eligible population including coverage among young adolescents (15-18 years) and precaution dose for health care workers, frontline workers and elderly with co-morbidities.
- Ensuring adherence to COVID Appropriate Behaviour.

Union Ministry of Health & FW continues to provide support to States/UTs to enhance preparedness and response capacities against COVID-19 and other public health emergencies. Funding support is also provided to States/UTs through National Health Mission, State Disaster Response Funds (SDRF) and Emergency COVID-19 Response and Preparedness packages. Under ECRP Phase II, a package of Rs. 23,123 crore (with Rs. 15,000 Cr as Central Component) has been approved. Of this, as on 31st January 2022, funds to the tune of Rs. 7245.95 crore have been released to States/UTs as part of Central component to strengthen health infrastructure to manage any surge in cases.

Omicron variant is the dominant variant in the country presently. The current surge of COVID-19 cases in the country is showing a sustained declining trend since 21st January 2022.

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 66
08 फरवरी, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में ऑमिक्रॉन के मामलों में चिंताजनक वृद्धि

***66: श्री टी.जी. वेंकटेशः**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में कोविड-19 के ऑमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों के प्रसार में चिंताजनक वृद्धि पर ध्यान दिया है जो लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में इस समस्या का निराकरण करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

08 फरवरी, 2022 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 66 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सार्स-कोव-2 वायरस के अत्यधिक म्यूटेटिड वैरियंट ओमीक्रोन वैरियंट की रिपोर्ट मिलने और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैरियंट ऑफ कनसर्न (वीओसी) के रूप में घोषित करने के साथ ही, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमनों के लिए अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया। जोखिम आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए, भारत में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिए गए वर्तमान दिशानिर्देशों में प्रस्थान से पहले और यहां पहुंचने के बाद अनिवार्य रूप से, 8वें दिन आरटी-पीसीआर जांच करवाने तथा 7 दिनों के लिए घर पर क्वारंटीन रहने का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं जैसे कि नियंत्रण और सर्विलांस, जांच, क्लीनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉल, कोविड उपरांत परिणाम आदि के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखे हुए है। एम्स, दिल्ली और भारतीय चिकित्सा संघ के सहयोग में सभी राज्यों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की उत्कृष्टता केंद्र पहल के अंतर्गत क्लीनिकल प्रबंधन प्रोटोकॉलों का प्रचार-प्रसार भी किया गया है।

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तैयारी और अनुक्रिया से जुड़े उपायों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर विषय विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करने के अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी समीक्षा बैठकें की जाती रही हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित क्रियाकलापों की सलाह दी गई है:

- समुदाय में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सख्त निगरानी।
- पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पता लगाना और इन पर 14 दिनों के लिए नजर रखना।
- पॉजिटिव नमूनों की तुरंत इनसाकोग प्रयोगशालाओं में जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना।
- जिन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामले उभरकर सामने आते हैं वहां की निरंतर निगरानी।
- राज्यों में कोविड-19 जांच की अवसंरचना को और सुदृढ़ करना और पर्याप्त संख्या में जांच कराकर मामलों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ बच्चों के मामलों के लिए ईसीआरपी-II के तहत स्वास्थ्य अवसंरचना (आईसीयू, ऑक्सीजन लगे बिस्तरों, वेंटीलेटरों आदि की उपलब्धता) की तैयारी सुनिश्चित करना और इसके तहत स्वास्थ्य अवसंरचना का उन्नयन करना।
- सभी पीएसए संयंत्रों को चालू करना, पर्याप्त साजो-सामान, औषधियां आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- छोटी उम्र के किशोरों (15-18 वर्ष) के साथ-साथ शेष पात्र जनसंख्या को कोविड-19 टीकाकरण और स्वास्थ्य परिचर्या कर्मियों, फ्रंटलाइन कर्मियों और सहरुग्णताओं वाले वृद्धजनों के लिए एहतियाती खुराक का टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- कोविड अनुरूप आदतों का पालन सुनिश्चित करना।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कोविड-19 और जन स्वास्थ्य की अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी और अनुक्रिया की क्षमताओं को बढ़ाने में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों

को सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य आपदा अनुक्रिया निधियों (एसडीआरएफ) और आपातकालीन कोविड-19 अनुक्रिया और तैयारी संबंधी पैकेजों (ईसीआरपी) के माध्यम से निधियन सहायता भी प्रदान की जाती है। ईसीआरपी चरण II के तहत, 23,123 करोड़ रुपए (केंद्रीय घटक के रूप में 15,000 करोड़ रुपए समेत) का पैकेज मंजूर किया गया है। इसमें से 31 जनवरी, 2022 तक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय घटक के रूप में 7245.95 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई हैं ताकि मामलों की संख्या में किसी भी उछाल से निपटने के लिए अपनी स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ कर सकें।

फिलहाल देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रमुख वेरिएंट है। देश में कोविड-19 के मामलों की संख्या में आए मौजूदा उछाल में 21 जनवरी, 2022 से लगातार गिरता रुझान देखा जा रहा है।

******

SHRI T.G. VENKATESH: Sir, my first supplementary question to the hon. Minister is that the manufacturing of vaccine for controlling Covid-19 disease has been successfully done by the Modi Government. It has successfully been administered to more than 100 crores people who are vaccinated now, and, globally, also, we are in a position to supply. But this vaccine is only preventive.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

SHRI T.G. VENKATESH: Spreading of virus will not be controlled only by masks. For this purpose, heap filters have to be installed. Is the Government going to take steps for installing heap filters in the Central Hall of Parliament and other places also?

डा. मनसुख मांडविया : उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह प्रश्न कोविड टीके के संदर्भ में है कि कोविड टीका कितना असरदार है, कितना असरदार नहीं है। सर, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि न केवल इंडिया में ICMR ने, बल्कि उसके अलावा विश्व के सभी scientific institutes ने कहा है कि टीका लगने से, vaccination हो जाने से हम कोविड में mortality और hospitality rate को कम कर सकते हैं और वह successfully कम हुआ है।

उपसभापति महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज देश में 97.5 परसेंट वयस्क लोगों को फर्स्ट डोज़ लग चुकी है और 77 परसेंट लोगों को सेकंड डोज़ लग चुकी है। विश्व की डेवलेप्ड कंट्रीज़ में भी 90 परसेंट से above भी फर्स्ट डोज़ नहीं लगी है। यह हिंदुस्तान ने लगाकर दिखाई है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हम Covid Crisis के सामने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका अच्छा नतीजा यह निकला कि जब थर्ड वेव आई या third surge आया, ऐसी स्थिति में ओमिक्रॉन के सामने लड़ने में यही टीकाकरण उपयोगी हुआ है। अभी दो दिन पहले आईसीएमआर की स्ट्डी आई है, उसके मुताबिक देश में जिन 99.3 परसेंट लोगों को कोविड हुआ था, चूंकि उनका टीकाकरण हो चुका था, इसलिए वे सुरक्षित रहे और यह हमारे लिए बहुत अच्छा indication है। विश्व के सामने हिंदुस्तान ने एक example स्थापित किया है कि इतना बड़ा देश, diversity, इतनी विवधता के बावजूद भी विश्व के सापेक्ष में भारत ने अच्छी तरह से Covid Crises के सामने लड़ाई लड़ी है।

SHRI T.G. VENKATESH: Sir, my second supplementary to the hon. Minister is: Is it true that Omicron-affected persons develop anti-bodies which can prompt the body's immune response to the virus and protect them from any variant of Covid-19 virus?

डा. मनसुख मांडविया : माननीय उपसभापति महोदय, कोविड टीका लगने से व्यक्ति के शरीर में एंटी बॉडीज़ डेवलेप होती हैं और जब कोविड वेरिएंट आते हैं, तो उनसे सुरक्षा देती हैं।

SHRI JOHN BRITTAS: Sir, is it a fact that numerous RTPCR tests which people have to undergo is becoming a big loot? I myself spent almost Rs. 25,000 in a month's time. Will the Government consider this fact and ensure that the charges for the RTPCR tests are reduced or made uniform or made free, like in other countries? Will the Government also consider that the money for RTPCR tests be spent from the PM CARES Fund from which two-thirds of the money is unspent?

(MR. CHAIRMAN *in the Chair.*)

डा. मनसुख मांडविया : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, वह आरटीपीसीआर टैस्ट के संबंध में है। आरटीपीसीआर के लिए आज तरह-तरह की टेक्नोलॉजीज़ उपलब्ध हैं और तरह-तरह की किट्स उपलब्ध हैं। जो लोग भारत सरकार के हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां उनका टैस्ट फ्री में होता है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां अलग-अलग किट के अनुसार अलग-अलग प्राइस के मुताबिक टैस्ट होता है। लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट, दोनों हॉस्पिटल्स में जाकर टैस्ट करवाते हैं। अगर लोग गवर्नमेंट फैसिलिटी का उपयोग करें, तो कोई खर्च नहीं लगेगा।

MR. CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy - not present. Shri Syed Zafar Islam.

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, हमारे देश में जिस तरह से वैक्सिनेशन हुआ है, उसके लिए सरकार को जितनी भी बधाई दी जाए, वह कम है। मैं एक बेसिक सवाल पूछना चाहता हूं। चूंकि अब स्कूल्स खुल रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चों का वैक्सिनेशन अभी नहीं हुआ है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि छोटे बच्चों पर ओमिक्रॉन का खतरा कितना है? अब स्कूल खुल गए हैं और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, इसलिए अगर इसके बारे में मंत्री जी गाइड कर दें, तो अच्छा होगा।

डा. मनसुख मांडविया : माननीय सभापति महोदय, किसको वैक्सीन देनी है और किसको नहीं देनी है, यह साइंटिफिक सुझाव के आधार पर डिसाइड किया जाता है। इसके लिए देश में NTAGI नाम से एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप बनाया हुआ है। एक्सपर्ट लोगों की टीम बार-बार बैठती है, समय-समय पर सुझाव देती है और सुझाव के आधार पर सरकार डिसीज़न लेती है। भारत सरकार ने पहले इसे 18 and above के लिए किया था और उसके बाद अब 15 से 18 की उम्र के बच्चों को टीका लगाने का अभियान चल रहा है। 15 से 18 वर्ष की उम्र के 67 परसेंट बच्चों को टीका लग चुका है और यह कार्य तेज गति से चल रहा है। जैसे-जैसे हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट टीम की ओपिनियन आएगी, उनकी ओपिनियन के आधार पर आगे का डिसीज़न लिया जा सकता है।

श्री सभापति : क्वेश्चन नम्बर 67.